penditure in the Central Government departments;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what steps have been taken so far for effecting economy in expenditure and with what results?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (c) Central Ministries/Departments have been advised to eliminate in essential and low priority items of expenditure through a process of prioritisation of their programmes and activities. Ministries have also been advised to effect economy in expenditure in various areas. These include restrictions on travel expenses, entertainment, internal seminars and conferences, publications, purchase of furniture/furnishing, fuel consumption, etc. Effect of these measures is reflected in the Revised Estimates 1989-90 which will be presented to Parliament alongwith the Budget for 1990-91.

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति के न्यायाधीश

350. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में इस समय कुल कितने कितने न्यायाधीश हैं और इनमें से कितने-कितने न्यायाधीश अनुसूचित जाति के हैं ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है । (**नीचे देखिए**) ।

विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	पदासीन न्यायाधीश	अनुसूचित जाति के न्यायाधीश
1.	इलाहाबाद	46	1
2.	आंध्र प्रदेश	17	—
3.	मुंबई	47	4
4.	कलकत्ता	40	—
5.	दिल्ली	21	—
6.	गुवाहाटी	12	—
7.	गुजरात	12	1
8.	हिमाचल प्रदेश	4	—
9.	जम्मू–कश्मीर	5	—
10.	कर्नाटक	19	1
11.	केरल	24	1
12.	मध्य प्रदेश	22	—
13.	मद्रास	20	1
14.	उड़ीसा	13	—
15.	पटना	28	—
16.	पंजाब और हरियाणा	18	—
17.	राजस्थान	18	—
18.	सिक्किम	2	—
	योग :	368	9